श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है।...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: उपसभापति महोदय, मैं डिमांड्स रखने के लिए लोक सभा में था। यह हमारा अपर हाउस है, गरिमामय हाउस है, इसे देखने के लिए दो एमओएस हमारे यहां उपस्थित थे, दोनों राज्य मंत्री।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह आते हैं, आते हैं।...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: कभी-कभी एप्पियर होंगे, बराबर एप्पियर होंगे, तो फिर आप कहेंगे कि नहीं चलेगा।...(व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: हम 11.00 से 12.00 बजे के लिए कह रहे हैं।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: ठीक है, ठीक है।...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: इसलिए महोदय, ...(व्यवधान)... आप हमारी बात सुन लीजिए। 12.00 बजे हमारा वहां था। ...(व्यवधान)... मैं बहुत पंक्चुअल रहता हूं।

[Shri Shamta Ram Laxman Naik]

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Supplementary Demands for Grants (Railways) 2007-2008.

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS) 2007-2008

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI LALU PRASAD): Sir, I lay on the Table a statement (in English and Hindi) showing the Supplementary Demands for Grants (Railways) for the year 2007-2008.

श्री रवि शंकर प्रसाद (बिहार): मंत्री जी, आप से प्रश्नों के उत्तर सुने हुए बहुत दिन हो गये हैं।...(व्यवधान)...

श्री लालू प्रसाद: अच्छा ठीक है।...(व्यवधान)...

श्री उपसभापति: वह उत्तर देंगे।

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS (RESOLUTIONS)

Constitution of a committee for recommending amendments to constitution for adding a new chapter on governance of coalition governments

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK (Goa): Sir, I beg to move the following Resolution:

"Having regard to the facts that—

(i) an era of coalition governments at the national and States has crept in;

(ii) Indian political scenario is not likely to change substantially in this respect in near future;

(iii) there is no mechanism at present which can effectively find solutions to the problems which arise out of coalition form of Government; and

(iv) there is a need to ensure that the nation does not suffer on account of delays, uncertainties under such dispensations;

this House resolves to constitute a Committee for the purpose of recommending amendments to the Constitution by way of adding a new chapter on the governance of coalition